



करेंट अफेयर्स

मध्य प्रदेश

अप्रैल

(संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश

➤ निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग, कमेटी और बोर्ड के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा	3
➤ प्रदेश में 730 पी.एम. श्री स्कूलों की स्थापना का अनुसमर्थन	3
➤ संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर ने सर्वाधिक बिजली उत्पादन का बनाया रिकार्ड	4
➤ राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश की तीन विभूतियों को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया	4
➤ मुख्यमंत्री ने 'हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना' का लोकार्पण किया	5
➤ प्रदेश के 5 हस्त-शिल्प उत्पाद सहित रीवा के सुंदरजा-आम को मिला जी.आई. टैग	5
➤ प्रदेश में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिये दूसरे समग्र पुनर्वास केंद्र (सीआरसी) की सेवाओं का उद्घाटन	9
➤ टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन में सतपुड़ा रिजर्व देश में द्वितीय तथा कान्हा रिजर्व पाँचवें स्थान पर	9
➤ स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने रायसेन में जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ	10
➤ मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू	11
➤ ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी को नैक रैंकिंग में मिला ए++ ग्रेड	11
➤ दुंगरिया माइक्रो सिंचाई और टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना को मिली मंजूरी	12
➤ राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित	12
➤ प्रोत्साहन योजना की अवधि 2024 तक बढ़ाई गई	13
➤ मुख्यमंत्री करेंगे यूनेस्को की उप-क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ	13
➤ राज्यपाल ने रेडक्रॉस के चलित स्वास्थ्य सेवा वाहन का किया शुभारंभ	14
➤ ग्वालियर में स्थापित होगी प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी और एयरोपोनिक्स लैब	14
➤ डॉ. अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना से जोड़ा गया	14
➤ मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ने वितरित किये महर्षि दधीचि पुरस्कार	15
➤ छिंदवाड़ा का गोदड़देव मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक घोषित	16
➤ प्रदेश में लागू किया जाएगा नया जुआ अधिनियम	16
➤ छात्रों में उद्यमी विश्वास और कौशल विकसित करने के लिये प्रारंभ होगा तेजस्वी कार्यक्रम	16
➤ प्रदेश में ट्रांसजेंडर समुदाय पिछड़ा वर्ग में शामिल	17
➤ मध्य प्रदेश पुलिस के दो प्रशिक्षण संस्थानों को मिलेगी यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी	18
➤ जल जीवन मिशन में जिला बुरहानपुर 'प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार' से सम्मानित	18
➤ निर्वाचन की राज्य स्तरीय आईकॉन नियुक्त हुई समाज सेविका थर्ड जेंडर संजना सिंह	19
➤ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ह्याट्सएप से बिल जमा करने वाली देश की पहली कंपनी	19
➤ सरोगेसी अधिनियम के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल	20
➤ मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभयारण्य होगा चीतों का नया घर	20
➤ मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 स्थगित	21
➤ कैबिनेट में पन्ना की दो सिंचाई परियोजना को मिली पुनर्निश्चित स्वीकृति	21
➤ राज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी उद्घाटित	21
➤ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में तीन दिवसीय इंटरनेशनल वाईल्ड लाईफ कॉन्फ्रेंस	22
➤ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले सात नए जज, अब संख्या बढ़कर हुई 37	23

मध्य प्रदेश

निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग, कमेटी और बोर्ड के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

31 मार्च, 2023 को मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर प्रदेश के निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग, कमेटी और बोर्ड के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को क्रमशः कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है।

प्रमुख बिंदु

- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित निगम/मंडल/प्राधिकरण/आयोग/कमेटी/बोर्ड के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है-
 - ◆ कृष्ण मोहन सोनी - अध्यक्ष, भोपाल विकास प्राधिकरण
 - ◆ वेद प्रकाश शर्मा - अध्यक्ष, योग आयोग
 - ◆ रामदयाल प्रजापति - अध्यक्ष, माटी कला बोर्ड
 - ◆ भागचंद उइके - अध्यक्ष, राज्य प्रवासी आयोग
 - ◆ भगवानदास गोंडाने - अध्यक्ष, श्रम कल्याण मंडल
 - ◆ घनश्याम पिरोनिया - अध्यक्ष, बाँस विकास प्राधिकरण
 - ◆ रामलाल रोतेले - अध्यक्ष, कोल विकास प्राधिकरण
 - ◆ रफत वारसी - अध्यक्ष, हज कमेटी
- निम्नलिखित निगम/मंडल/प्राधिकरण/आयोग/कमेटी/बोर्ड के अध्यक्षों को तथा कैबिनेट मंत्री उपाध्यक्षों को राज्य के राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है-
 - ◆ नंदराम कुशवाहा - उपाध्यक्ष, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम
 - ◆ सुनील पांडे - उपाध्यक्ष, भोपाल विकास प्राधिकरण
 - ◆ अनिल अग्रवाल 'लिली'- उपाध्यक्ष, भोपाल विकास प्राधिकरण
 - ◆ राकेश 'गोलू'शुक्ला - उपाध्यक्ष, इंदौर विकास प्राधिकरण

प्रदेश में 730 पी.एम. श्री स्कूलों की स्थापना का अनुसमर्थन

चर्चा में क्यों ?

4 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई जिसमें मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 730 पी.एम. श्री स्कूलों की स्थापना का अनुसमर्थन किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में अधिकतम 02 स्कूल (313 विकासखंडों में 626) और 52 जिलों के नगरीय निकायों में 104 स्कूल, इस तरह अधिकतम 730 स्कूलों को पी.एम. श्री स्कूल के रूप चिह्नित किया जाएगा।

- चिह्नित स्कूलों में से एक प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा पहली से आठवीं) एवं एक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये संचालित होगा। पी.एम. श्री स्कूल की लागत 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य द्वारा वहन की जाएगी।
- सभी 730 पी.एम. श्री स्कूलों पर प्रतिवर्ष 277 करोड़ 40 लाख रुपए का व्यय भार आएगा, जिसमें से राज्यांश 110 करोड़ 96 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगा।
- यह परियोजना 5 वर्ष की है और इस अवधि में 554 करोड़ 80 लाख रुपए का व्यय भार राज्य सरकार पर आएगा। योजना के 5 वर्ष बाद इसका संचालन पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि पी.एम. श्री स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के समग्र रूप से अनुपालन के साथ शिक्षा की गुणवत्ता, समानता एवं शिक्षा सुविधा की पहुँच का समावेश किया जाएगा। ये स्कूल अन्य विद्यालयों के लिये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होंगे।

संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर ने सर्वाधिक बिजली उत्पादन का बनाया रिकार्ड

चर्चा में क्यों ?

4 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 8758.8 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन के साथ 74.6 प्रतिशत प्लांट लोड फेक्टर (पीएलएफ) अर्जित कर विद्युत गृह बिरसिंगपुर के इतिहास में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन और सर्वोच्च पीएलएफ अर्जित करने का रिकार्ड बनाया है।

प्रमुख बिंदु

- इससे पूर्व इस विद्युत गृह ने वर्ष 2018-19 में कुल 8680.7 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन और 74 प्रतिशत पीएलएफ अर्जित किया था।
- संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर की 5 इकाइयों का वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल विशिष्ट तेल खपत 0.55 मिलीलीटर प्रति यूनिट और संयंत्र सहायक खपत (ऑक्जलरी कंजम्पशन) 8 प्रतिशत रही।
- उल्लेखनीय है कि संजय गांधी ताप विद्युत गृह में 210 मेगावाट क्षमता की 4 और 500 मेगावाट क्षमता की एक इकाई है। 210 मेगावाट क्षमता की 4 इकाइयों क्रमशः 7 अक्टूबर, 1993; 26 मई, 1994; 1 सितंबर, 1999 एवं 1 अप्रैल, 2000 को क्रियाशील हुई थीं। 500 मेगावाट की इकाई क्रमांक-पाँच 27 अगस्त, 2008 को क्रियाशील हुई थी। इस विद्युत गृह की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 1340 मेगावाट है।
- संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर की 500 मेगावाट क्षमता की इकाई ने भी वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 3927.6 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन एवं 89.7 प्रतिशत पीएलएफ अर्जित करते हुए अभी तक का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन और सर्वाधिक पीएलएफ अर्जित करने का रिकार्ड कायम किया।
- इस इकाई की कुल विशिष्ट तेल खपत 0.24 मिलीलीटर प्रति यूनिट रही। यह अभी तक की न्यूनतम तेल खपत है।

राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश की तीन विभूतियों को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार (द्वितीय संस्करण) में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की तीन विभूतियों को वर्ष 2023 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में वर्ष 2023 के लिये 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और सैंतालिस पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किये गए।
- कला के क्षेत्र में रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार तथा चिकित्सा के क्षेत्र में डॉ. मुनीश्वर चंद्र डावर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
- झाबुआ के कलाकार दंपति रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार पिछले 3 दशकों से झाबुआ की सुप्रसिद्ध जनजातीय गुड़िया और पारंपरिक जनजातीय परिधान के निर्माण में लगे हुए हैं।
- जबलपुर के चिकित्सक डॉ. डावर किफायती इलाज से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा कर रहे हैं।



मुख्यमंत्री ने 'हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना' का लोकार्पण किया

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिले के ग्राम बहेरिया में 116 करोड़ 78 लाख रुपए लागत की 'हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना' का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहडोल जिले की हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से 37 ग्रामों में किसानों की 7481 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा, जिससे किसानों की जिंदगी बदलेगी और उनके खेत लहलहा उठेंगे।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शहडोल जिले के ही ब्यौहारी में 327.51 करोड़ रुपए लागत की भन्नी वृहद् सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। किसानों के खेत तक पानी पहुँचाने के लिये बड़े पैमाने पर कार्य हो रहा है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा निरंतर बढ़ रहा है।

प्रदेश के 5 हस्त-शिल्प उत्पाद सहित रीवा के सुंदरजा-आम को मिला जी.आई. टैग

चर्चा में क्यों ?

6 अप्रैल, 2023 को प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा मध्य प्रदेश के 6 उत्पादों (5 हस्त-शिल्प उत्पाद और एक उद्यानिकी उत्पाद) को जी.आई. टैग प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इन 6 उत्पादों में डिंडौरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कार्पेट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वारासिओनी की साड़ी और रीवा के सुंदरजा-आम शामिल हैं।

- विदित है कि यह पहला अवसर है कि जब एक साथ प्रदेश के इतने उत्पादों को जी आई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या 19 हो गई है।
- अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि जी.आई. टैग (जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग) एक प्रकार का लेवल है, जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है, जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।
- उन्होंने कहा कि नाबार्ड टेक्सटाइल कमेटी और वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से राज्य सरकार ने कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के साथ स्थानीय उत्पादक संस्थाओं के समन्वय से यह सफलता प्राप्त की है।



डिंडौरी की गोंड पेंटिंग



ग्वालियर का कार्पेट



उज्जैन की बाटिक प्रिंट



जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट



बालाघाट की वारासिओनी की साड़ी



रीवा का सुंदरजा-आम

प्रदेश में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिये दूसरे समग्र पुनर्वास केंद्र (सीआरसी) की सेवाओं का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

8 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के छतरपुर के महलानगेट स्थित पुराने तहसील भवन में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिये समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) की सेवाओं का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह सीआरसी नवाचार एवं शिक्षा का एक केंद्र बनेगा और दिव्यांगजनों के लिये बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन को संभव बनाने हेतु जनशक्ति एवं अनुसंधान संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा ताकि दिव्यांगजन समाज के विकास में योगदान कर सकें।
- उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को एक छत के नीचे लाकर और संबद्ध सेवाओं की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित कर छतरपुर और उसके आसपास के इलाकों में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के समक्ष समाज में पेश आने वाली कुछ सबसे कठिन चुनौतियों से निपटने की भी योजना है।
- समारोह में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह नया सीआरसी दिव्यांगजनों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करेगा और मध्य प्रदेश राज्य में मानव संसाधन विकसित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छतरपुर जिले में प्रदान की गई दो हेक्टेयर भूमि पर सीआरसी-छतरपुर के भवन का निर्माण भी शीघ्र शुरू किया जाएगा।
- यह नया सीआरसी दिव्यांगजनों के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के अलावा दिव्यांगता की 21 श्रेणियों के लिये पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करेगा।
- दिव्यांगजनों के लिये सहायता एवं उपकरण और यूनिवर्सल आइडेंटिटी (यूडीआईडी) कार्ड वितरित करने के लिये शिविर आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। यह कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। सुगम्य भारत अभियान की दिशा में नई पहल की जाएगी। यह अभियान दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने हेतु देश भर में जारी है।
- सीआरसी-छतरपुर द्वारा दिव्यांग छात्रों को बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा जारी रखने के लिये वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।
- गौरतलब है कि भोपाल, अहमदाबाद और नागपुर स्थित सीआरसी के अलावा सीआरसी-छतरपुर का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत मुंबई स्थित अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन) एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) के पास है।

टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन में सतपुड़ा रिजर्व देश में द्वितीय तथा कान्हा रिजर्व पाँचवें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

9 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (MEE) के पाँचवें दौर की सारांश रिपोर्ट जारी की, जिसमें देश के 51 टाइगर रिजर्व में टॉप 5 टाइगर रिजर्व में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को द्वितीय एवं कान्हा रिजर्व को पाँचवां स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि पहले स्थान पर केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व रहा। उसका प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन स्कोर 94.38% रहा। वहीं दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और तीसरे स्थान पर कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व रहा। दोनों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन स्कोर 93.18% रहा।

- इसके अलावा मध्य प्रदेश के बालाघाट के कान्हा टाइगर रिजर्व को पाँचवाँ और सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व को आठवाँ रैंक मिला है।
- सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यह रैंक बेहतर प्रबंधन, कार्य, बेहतर टीम के चलते प्राप्त हुआ है।
- इस रिपोर्ट में वर्ष 2022 में अधिसूचित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (राजस्थान) और रानीपुर टाइगर रिजर्व (उत्तर प्रदेश) को शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं।
- गौरतलब है कि प्रबंधन प्रभावशीलता और मूल्यांकन थर्ड पार्टी असेसमेंट है, जो 4 साल में एक बार अपने सर्वे कर आँकड़े जारी करती है। सर्वे में मूल्यांकन टीम दस्तावेजों, जमीनी कार्य, फील्ड स्टाफ और हितधारकों के साथ बातचीत, वन्यजीवों की वृद्धि और सुरक्षा और प्रबंधन प्रणालियों के स्तर का मूल्यांकन करती है।
- समुदाय, पर्यटन को सुव्यवस्थित करना, पार्क और जानवरों दोनों के लिये बेहतर बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ सक्रिय वन्यजीव प्रबंधन कुछ ऐसे ही मापदंड हैं, जिनके आधार पर पार्क को आँका जाता है।
- सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
 - ◆ नर्मदापुरम जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह डेक्कन बायो-जियोग्राफिक क्षेत्र का हिस्सा है। अभूतपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह देश की प्राचीनतम वन संपदा है, जो बड़ी मेहनत से संजोकर रखी गई है।
 - ◆ हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों की कुछ प्रजातियाँ और दक्षिण के वनों में पाई जाने वाली कुछ प्रजातियाँ, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में भी भरपूर पाई जाती है। कुछ प्रजातियाँ जैसे कीटभक्षी घटपर्णी, बाँस, हिसालू, दारूहल्दी सतपुड़ा और हिमालय दोनों जगह मिलती हैं।
 - ◆ सतपुड़ा की पहाड़ी श्रृंखला में 1500 से 10 हजार वर्ष पुराने 50 शैलाश्रय हैं। प्राकृतिक महत्त्व के साथ इनका पुरातात्विक महत्त्व भी है। इस प्रकार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देश के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा है।
 - ◆ यहाँ अकाई वट, जंगली चमेली जैसी वनस्पतियाँ भी हैं, जो अन्यत्र नहीं या बहुत कम पाई जाती हैं। वनस्पतियों के अतिरिक्त 14 ऐसे वन्य-जीव हैं जिनका जीवन आज खतरे में हैं, फिर भी यहाँ उनका रहवास बना हुआ है, जैसे- उड़न गिलहरी।
 - ◆ बाघों की उपस्थिति और उनके प्रजनन क्षेत्र के रूप में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध है। यह रिजर्व बाघों की अच्छी उपस्थिति वाले मध्य भारत के क्षेत्रों में से एक है।
 - ◆ देश के बाघों की संख्या का 17 प्रतिशत और बाघ रहवास का 12 प्रतिशत क्षेत्र सतपुड़ा में आता है।
 - ◆ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एक प्रकार से हिमालय और पश्चिमी घाट के बीच वन्य-जीव की उपस्थिति का सेतु बनाता है। यह मालाबार व्हिसलिंग ग्रश अर्थात कस्तूरा पक्षी, दूधराज, मालाबार पाइड हार्नबिल अर्थात धनेश पक्षी के लिये भी आदर्श रहवास है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने रायसेन में जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

10 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने राज्य स्तरीय जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान का रायसेन जिला चिकित्सालय में शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस टीकाकरण अभियान के पहले चरण में रायसेन और विदिशा जिले में 10 से 30 अप्रैल तक 1 से 15 वर्ष आयु के शत-प्रतिशत बच्चों को इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन लगाई जाएगी।
- गौरतलब है कि जापानी इंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसके टीकाकरण से इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षा मिलती है।
- टीकाकरण टीम जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान में शत-प्रतिशत बच्चों को टीका लगाना सुनिश्चित करेगी।

मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में किया जाएगा साथ ही इस योजना की मॉनिटरिंग के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
- इस योजना की अवधि 2 वर्ष (2023-24 एवं वर्ष 2024-25) की होगी। इन 2 वर्षों में योजना में 23 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय किये जाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी/शासकीय संस्थाओं से 80 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किये जाएंगे।
- मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत मिलेट फसलों के उत्पादन, प्र-संस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिये किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण होंगे। मिलेट को बढ़ावा देने के लिये जिला एवं राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, सेमीनार, फूड फेस्टिवल, रोड-शो किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि मिलेट अनाज की फसलें कभी प्रदेश की खान-पान की संस्कृति के केंद्र में थी। वर्तमान में इन फसलों के पोषक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इन फसलों की खेती प्रायः कम उपजाऊ क्षेत्रों में की जाती है।
- वर्तमान में उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से मिलेट फसलों की माँग बढ़ रही है। कोदो, कुटकी, रागी, सांवा जैसी फसलें स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक हैं। इन मिलेट फसलों के महत्व के दृष्टिगत इनको पोषक अनाज का दर्जा दिया गया है।
- इन फसलों के अनाज आयरन, कैल्शियम, फाइबर आदि से भरपूर होते हैं साथ ही इनमें वसा का प्रतिशत भी कम होता है, जिससे हृदय रोगी एवं डायबिटीज रोगियों के द्वारा इनका उपयोग सुरक्षित पाया गया है। इसलिये किसानों के बीच मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने एवं मिलेट फसलों से तैयार व्यंजनों का प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।
- मध्य प्रदेश में कोदो-कुटकी, ज्वार एवं रागी के क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। साथ ही मिलेट फसलों के बढ़ते बाजार के दृष्टिगत मूल्य संवर्धन की संभावना भी काफी अधिक है।

ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी को नैक रैंकिंग में मिला ए++ ग्रेड

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय को नैक कमेटी द्वारा ए++ ग्रेड दिया गया है। इसके साथ ही जीवाजी विश्वविद्यालय प्रदेश का ऐसा इकलौता विश्वविद्यालय बन गया है जिसे यह उच्च ग्रेड प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि नैक कमेटी की 5 सदस्य टीम ने 27 से 29 मार्च, 2023 तक जीवाजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया था।
- वहीं भोपाल के महारानी लक्ष्मी बाई महाविद्यालय को नैक रैंकिंग में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। शिवपुरी के पीजी महाविद्यालय ने एक कदम आगे बढ़ाकर रैंकिंग में बी+ ग्रेड प्राप्त किया है।
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नैक में सम्मिलित होने वाले महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता में रखकर प्रशिक्षण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ति की गई। महाविद्यालयों का इंटरनल एसेसमेंट कराया गया।
- उल्लेखनीय है कि ई-लायब्रेरी, वाई-फाई परिसर, शिक्षकों का प्रशिक्षण, ई-कंटेंट, इन्वयवेशन सेंटर, हास्टल और विद्यार्थियों का परफार्मेंस, शिक्षकों के शोधकार्य के आधार पर मूल्यांकन कर नैक ग्रेडिंग तय की जाती है।
- गौरतलब है कि नैक या नेशनल असेसमेंट एंड एक्कीडेशन काउंसिल (राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्) का काम देशभर की यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी परखना और उनको रेटिंग देना है।

- यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं उनके मुताबिक सभी शिक्षण संस्थानों को नैक से मान्यता पाना जरूरी है। अगर कोई संस्थान इससे मान्यता नहीं लेता है तो उसे किसी गवर्नमेंट पॉलिटी का फायदा नहीं मिलता है।
- महाविद्यालय/विश्वविद्यालय या कोई और उच्च शिक्षण संस्थान सभी मानकों को पूरा करने पर नैक ग्रेडिंग के लिये आवेदन करता है। आवेदन के बाद नैक की टीम संस्थान में आती है और इंस्पेक्शन करती है। इस दौरान वे एजुकेशनल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज एटमॉस्फियर जैसे विभिन्न पहलुओं की जाँच करते हैं। अगर नैक की टीम संतुष्ट होती है तो कॉलेज को उसी आधार पर सीजीपीए दिये जाते हैं, जिसके आधार पर बाद में ग्रेड दिया जाता है।
- एक बार नैक ग्रेडिंग मिल जाने के बाद ये 4 साल के लिये मान्य होता है। 4 साल बाद फिर से रेटिंग दी जाती है। नैक में टेम्पेरी ग्रेडिंग की भी व्यवस्था है, जिसमें दो साल के लिये ग्रेडिंग दी जाती है। अगर कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नैक द्वारा दिये गए ग्रेड से खुश नहीं है तो 6 महीने के बाद फिर से ग्रेड के लिये आवेदन कर सकता है।

डुंगरिया माइक्रो सिंचाई और टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना को मिली मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद ने डुंगरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना और टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना को पुनरीक्षित मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- इन दो परियोजनाओं से लगभग 6 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र सिंचित किया जा सकेगा।
- ग्वालियर जिले में टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी लघु सिंचाई परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना की अनुमानित लागत 44 करोड़ 90 लाख रुपए है। इस परियोजना से 3 हजार 700 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।
- वहीं डुंगरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना उज्जैन जिले के महिदपुर विकासखंड में क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित है। इस परियोजना में 9.37 एम.सी. एम. के बाँध निर्माण और पाइप नहर का निर्माण किया जाएगा।
- इस परियोजना की लागत 104 करोड़ 74 लाख रुपए है। इससे 8 ग्राम में 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की सिंचाई होगी। इस परियोजना में 1.10 मेगावाट विद्युत खपत होगी।

राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक कृषि के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति (एसएलईसी) का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस नवगठित समिति में अपर मुख्य सचिव कृषि, आयुक्त उद्यानिकी, आयुक्त पंचायती राज, आयुक्त ग्रामीण विकास, संचालक अनुसंधान सेवाएँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, निदेशक अनुसंधान सेवाएँ, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, संचालक भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल और संचालक मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था सदस्य रहेंगे।
- इस समिति में प्रगतिशील कृषक विशेषज्ञ सदस्य और संचालक कृषि सदस्य सचिव होंगे।
- राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति राज्य नोडल विभाग द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य-योजना का अनुमोदन करेगी।
- साथ ही यह समिति नोडल और अन्य संबंधित विभागों के साथ नियमित बैठक कर योजना घटकों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।

प्रोत्साहन योजना की अवधि 2024 तक बढ़ाई गई

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2023 को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र में आने वाले ग्रामीण वितरण केंद्रों में राजस्व संग्रहण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लाइन कर्मचारियों एवं मीटर रीडर्स के लिये जारी की गई प्रोत्साहन योजना की अवधि 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लागू की गई प्रोत्साहन योजना के अच्छे परिणामों को देखते हुए इसकी अवधि को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाया गया है।
- इस योजना से बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल भुगतान की सुविधा में विस्तार के साथ ही उपभोक्ता संतुष्टि में भी वृद्धि परिलक्षित हुई है।
- गौरतलब है कि इस योजना में कंपनी द्वारा ग्रामीण वितरण केंद्रों के लाईन कर्मचारी एवं मीटर रीडर द्वारा 250 से अधिक देयकों का राजस्व संग्रहण करने पर योजना के प्रावधान अनुसार निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 लाख 58 हजार 365 उपभोक्ताओं से 91 करोड़ 42 लाख रुपए का राजस्व संग्रहण कार्मिकों द्वारा किया गया है। कुल 162 पात्र कार्मिकों को लगभग 24 लाख 60 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है।

मुख्यमंत्री करेंगे यूनेस्को की उप-क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

13 अप्रैल, 2023 को प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूनेस्को, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय पुरातत्त्व संरक्षण और पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा संयुक्त रूप से भोपाल में विश्व विरासत पर उप-क्षेत्रीय सम्मेलन (सब-रीजनल कॉन्फ्रेंस) का 17 अप्रैल को शुभारंभ करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि दो दिवसीय सम्मेलन के लिये भोपाल पहुँच रहे प्रतिनिधि 16 अप्रैल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल साँची का भ्रमण करेंगे। 17 एवं 18 अप्रैल को कई सत्र आयोजित किये जाएंगे।
- भारत सहित भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका एवं देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों एवं आगामी रणनीति जैसे विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।
- कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विश्व धरोहरों के संरक्षण की दिशा में पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों और अगले 50 वर्षों के संबंध में मंथन होगा, जिसका केंद्र विश्व विरासत और सतत् विकास, विश्व विरासत और सतत पर्यटन, विश्व विरासत और वैश्विक रणनीति, ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य जैसे विषय होंगे।
- सम्मेलन में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण पर मंथन होगा।
- उल्लेखनीय है कि नवंबर 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की 50वीं वर्षगाँठ मनाई गई थी। गत 50 वर्षों में सांस्कृतिक विरासत का अर्थ 'स्मारक केंद्रित' से परिवर्तित होकर 'लोक केंद्रित' (People Centric) एवं 'समग्र दृष्टिकोण' (Holistic approach) पर केंद्रित हो चुका है। ऐतिहासिक नगर, औद्योगिक विरासत, ऐतिहासिक मार्ग, ऐतिहासिक परिदृश्य इत्यादि नए आयाम जुड़ चुके हैं।
- मध्य प्रदेश ने यूनेस्को के साथ मिलकर इस दिशा में अनेक प्रयास किये हैं जिनमें HUL (ग्वालियर एवं ओरछा) प्रोजेक्ट, 4 ऐतिहासिक/पर्यटन स्थलों का यूनेस्को विश्व धरोहरों की संभावित सूची में चयन आदि मुख्य हैं। HUL प्रोजेक्ट हेतु यूनेस्को द्वारा साउथ एशिया देशों में प्रथम बार ग्वालियर एवं ओरछा का चयन कर अनुशंसा की गई।

राज्यपाल ने रेडक्रॉस के चलित स्वास्थ्य सेवा वाहन का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

13 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राजभवन में भारतीय रेडक्रास सोसायटी के चलित चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा वाहन का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि रेडक्रॉस म.प्र. राज्य शाखा द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर स्वास्थ्य सेवा वाहन का संचालन भोपाल में किया जा रहा है।
- रेडक्रास राज्य शाखा के चेयरमेन डॉ. गगन कोल्हे ने बताया कि चलित स्वास्थ्य सेवा वाहन के उपयोग से भोपाल महानगर के दूरस्थ अंचल की बस्तियों में नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।
- सेवा वाहन द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के साथ संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों के लिये जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
- वाहन से स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री का भी वितरण किया जाएगा।

ग्वालियर में स्थापित होगी प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी और एयरोपोनिक्स लैब

चर्चा में क्यों ?

13 अप्रैल, 2023 को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी और एयरोपोनिक्स लैब की स्थापना ग्वालियर में होगी।

प्रमुख बिंदु

- किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, राज्य कृषि विपणन बोर्ड और उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग की संयुक्त कार्य-योजना में सम्मिलित हाईटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी और एयरोपोनिक्स लैब की स्थापना के बारे में मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
- राज्य मंत्री कुशवाहा ने बताया कि उद्यानिकी विभाग के प्रस्ताव पर भोपाल में फ्लावर डोम निर्माण को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके लिये कार्य-योजना तैयार की गई है।
- राज्य मंत्री कुशवाहा ने कहा कि लैब का कार्य अगले माह के पहले सप्ताह में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कृषि, मंडी बोर्ड एवं उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण विभाग के समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिये कहा। साथ ही चैन फेंसिंग योजना को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिये।

डॉ. अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना से जोड़ा गया

चर्चा में क्यों ?

14 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों, उनकी जन्म-भूमि महु, शिक्षा-भूमि लंदन, दीक्षा-भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण-भूमि दिल्ली तथा चौत्य भूमि मुंबई को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना से जोड़ा गया है।

प्रमुख बिंदु

- बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर की जन्म-भूमि महु आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये महु में सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिये अब सेना से साढ़े तीन एकड़ भूमि के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है।
- यह भूमि डॉ. बाबा साहेब मेमोरियल समिति को लीज पर देकर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये धर्मशाला तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएंगी।

- उल्लेखनीय है कि धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से अंबेडकर जन्मस्थली महु, शिक्षा-भूमि लंदन में 10 किंग हेनरीज रोड स्थित स्मारक, दीक्षा-भूमि-डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ग्रंथालय एवं शोध केंद्र नागपुर, महापरिनिर्माण भूमि- डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली, चौत्य-भूमि डॉ. अंबेडकर स्मारक मुंबई को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना नियम 2012 में जोड़ा गया है।
- विदित है कि अधिसूचना में उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित संत रविदास मंदिर को भी तीर्थ-दर्शन योजना में शामिल किया गया है।

मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ने वितरित किये महर्षि दधीचि पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

18 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने दिव्यांगजन के उत्थान और उन्नति के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को दधीचि पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मंत्री ने सामाजिक न्याय विभाग में 16 नव-नियुक्त सहायक संचालक को नियुक्ति-पत्र भी प्रदान किये।
- मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने श्रवण-बाधित दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2012-13 का प्रथम पुरस्कार पीथमपुर जिला धार के मनोज द्विवेदी को दिया। फ्लेक्सीटफ इंटरनेशनल नामक अपनी संस्था में मनोज द्विवेदी ने 150 से अधिक दिव्यांगजनों को रोजगार देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है।
- श्रवण-बाधित दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2013-14 का पुरस्कार जबलपुर की डॉ. शिरीष जामदार को दिया गया। वे पिछले 20 साल से दिव्यांगजनों के व्यवसायिक पुनर्वास और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम निःस्वार्थ भाव से कर रही हैं। जामदार हॉस्पिटल में दिव्यांगजनों को निःशुल्क सर्जरी और उपचार की सुविधा भी दे रही हैं। वे शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सहायक कृत्रिम अंग और उपकरण भी वितरित करवाने में योगदान देती हैं।
- सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान की रचना करने वाले इंदौर के ज्ञानेंद्र पुरोहित को श्रवण-बाधित दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2014-15 का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके सांकेतिक राष्ट्रगान को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। ज्ञानेंद्र पुरोहित ने विशेष रूप से जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्र में श्रवण-बाधित बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाने और विभिन्न शासकीय सेवा में रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- श्रवण-बाधित दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2015-16 का दधीचि पुरस्कार जबलपुर के विवेक चतुर्वेदी को दिया गया। विवेक चतुर्वेदी ने श्रवण-बाधित युवाओं को डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रशिक्षण, रोजगार एवं आजीविका की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये केंद्र शासन के कार्यक्रम में रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण भी दिलाया। उन्होंने श्रवण-बाधितों द्वारा संचालित 'डेफग्राफिक्स'की स्थापना और व्यवसाय के लिये भी भरपूर सहायता की।
- विश्व का 5वाँ और भारत का पहला ब्रेल स्क्रिप्ट अरबी केंद्र स्थापित करने वाली इंदौर की कु. राबिया खान को दृष्टि-बाधित दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2015-16 का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने वर्ष 2011 में इंदौर में अरबी केंद्र स्थापित किया था। दृष्टिहीनों के लिये मदरसा नूर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करने वाली कु. राबिया खान दृष्टिहीन छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक और व्यावसायिक मुख्य धारा में लाने के लिये लगातार प्रयासरत हैं।
- मानसिक मंदता दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2015-16 का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले उज्जैन के जगदीश प्रसाद शर्मा ने 25 हजार से अधिक मानसिक अविकसित दिव्यांगों को बौद्धिक परीक्षण के बाद प्रमाण-पत्र दिलवाया। मानसिक रूप से अविकसित 3572 छात्र को विद्यालय में प्रवेश, छात्रवृत्ति और स्पेशल एजुकेशन सुविधा दिलवाई। उन्होंने 495 दिव्यांग को व्यवसाय से जोड़कर आत्म-निर्भर बनाया और 2875 लोगों को दिव्यांगों के लीगल गार्जियनशिप दिलाई।
- स्वयं दिव्यांग होने के बावजूद दिव्यांगजनों के लिये उद्दीप सोशल वेलफेयर सोसायटी की स्थापना करने वाली पूनम श्रोती को अस्थि-बाधित दिव्यांगता श्रेणी वर्ष 2019-20 का प्रथम पुरस्कार दिया गया। वह दिव्यांगजनों की शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिये कार्य कर रही हैं।

- स्वयं नेत्रहीन होने के बावजूद दिव्यांगजनों के लिये रोजगार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने वाले भोपाल के उदय हतवलने को दृष्टि-बाधित दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2019-20 प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। उदय हतवलने, दृष्टि-बाधितों की शिक्षा एवं सामाजिक समायोजन के लिये विशेष रूप से प्रयासरत हैं।
- नर्मदापुरम की आरती दत्ता को मानसिक मंदता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2019-20 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरती दत्ता ऑटिज्म, सेरेबल पॉल्सी, मानसिक मंदता का गहन अध्ययन कर इससे ग्रसित दिव्यांगजनों को आत्म-निर्भर बनाते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और पुनर्वास का महत्त्वपूर्ण काम कर रही हैं।

छिंदवाड़ा का गोदड़देव मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक घोषित

चर्चा में क्यों ?

18 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा छिंदवाड़ा के गोदड़देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गोदड़देव मंदिर छिंदवाड़ा जिले की तहसील चांद के नीलकंठी कला क्षेत्र में स्थित है।
- संस्कृति विभाग द्वारा मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम-1964 के तहत इसे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।
- गौरतलब है कि कलचुरियों के समकालीन एवं राज्य सीमा से लगे होने के कारण इस मंदिर का वास्तुशिल्प लगभग कलचुरि स्थापत्य से मिलता है। इसका निर्माण लगभग 13वीं सदी में हुआ।
- भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर भूमि शैली का है। भूविन्यास में गर्भ गृह, अंतराल एवं मंडप हैं। मंदिर का जंघा तक का पृष्ठ भाग अपने मूल स्वरूप में है। गर्भ गृह भूतलीय है, जिसमें शिवलिंग स्थापित है। वहाँ तक जाने के लिये सोपान है। अंतराल की रथिकाओं में गौरी व भैरव की प्रतिमाएँ स्थापित हैं। द्वार शाखा में सप्त मात्राएँ उत्कीर्ण हैं।
- गर्भ गृह एवं मंडप के ध्वस्त होने पर स्थानीय लोगों के द्वारा जीर्णोदार कराया गया है। मंदिर परिसर में मंडप के स्तंभ दृष्टव्य है। एक स्तंभ पर देवनागरी में संस्कृत भाषा के अस्पष्ट लेख हैं। इस मंदिर से कुछ दूरी पर दो और मंदिरों के भग्नावशेष हैं।

प्रदेश में लागू किया जाएगा नया जुआ अधिनियम

चर्चा में क्यों ?

19 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि राज्य शासन ने वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर 'मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023' बनाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग बड़ी समस्या है। वर्तमान में प्रदेश में जुआ अधिनियम 1876 लागू है। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है।
- नए अधिनियम में ऑनलाइन गैम्बलिंग के विरुद्ध पर्याप्त प्रावधान शामिल किये जाएंगे, जिससे इन गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को दंडित किया जा सके।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि चिटफंड कंपनियों पर प्रभावी कार्यवाही और प्रभावित लोगों का पैसा लौटाने के काम की निगरानी के लिये पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष सेल गठित किया जाएगा।

छात्रों में उद्यमी विश्वास और कौशल विकसित करने के लिये प्रारंभ होगा तेजस्वी कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

20 अप्रैल, 2023 को मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों में उद्यमी विश्वास एवं कौशल विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किये गए तेजस्वी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये बहुपक्षीय एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- सह समझौता पत्र (MOU) आयुक्त लोक शिक्षण, राज्य ओपन स्कूल एवं सहयोगी संस्था उद्यम लर्निंग फाउंडेशन और द एजुकेशन एलायंस के बीच हस्ताक्षरित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि तेजस्वी कार्यक्रम के तहत छात्रों को विद्यालयीन समय से ही नवीन उद्योगों और स्व व्यवसाय की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके लिये पृथक पाठ्यक्रम भी विकसित किया गया है।
- विद्यालयों में इस पाठ्यक्रम के आधार पर सप्ताह में तीन दिन 40-40 मिनट की विशेष कक्षाएँ संचालित की जाएंगी।
- इसके साथ ही विभिन्न नवाचारी व्यवसायों पर आधारित अनुभव आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रोजेक्ट कार्य भी संचालित होंगे। इसके लिये आवश्यक लागत राशि भी कार्यक्रम अंतर्गत शासन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे शालेय विद्यार्थी स्व-रोजगार और नये उद्यमों की स्थापना हेतु प्रेरित हो सकेंगे।
- इस अवसर पर प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शर्मा ने कहा कि शाला स्तर से ही विद्यार्थियों में चुनौतियों का सामना करने की योग्यताएँ एवं व्यवसायिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिये तेजस्वी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि प्रायोगिक तौर पर यह कार्यक्रम अभी प्रदेश के दो महानगरों भोपाल और इंदौर के शासकीय विद्यालयों की कक्षा नवमीं और ग्यारहवीं के विद्यार्थियों के लिये प्रारंभ किया जा रहा है जिसे भविष्य में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के मध्य संपूर्ण प्रदेश में संचालित किया जा सकेगा।
- आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में उद्यमी विश्वास और 21वीं सदी के कौशल विकसित करना है ताकि वे जीवन की चुनौतियों के लिये बेहतर रूप से तैयार हो सकें।
- उन्होंने बताया कि 'तेजस्वी एमपी कार्यक्रम' पाठ्यक्रम के अंतर्गत भोपाल और इंदौर के 301 शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं के लगभग 44,780 विद्यार्थी तथा 'तेजस्वी एमपी सामाजिक और व्यवसायिक नवाचार चौलेंज कार्यक्रम' में इन्हीं दोनों नगरों के 176 विद्यालयों के 11वीं कक्षा के 22,738 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

प्रदेश में ट्रांसजेंडर समुदाय पिछड़ा वर्ग में शामिल

चर्चा में क्यों ?

19 अप्रैल, 2023 को राज्य शासन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी।

प्रमुख बिंदु

- ट्रांसजेंडर (किन्नर) समुदाय को मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम-1995 के तहत जोड़ा गया है।
- विदित है कि प्रदेश में विकास की मुख्यधारा से अलग चल रहे किन्नर (ट्रांसजेंडर) समुदाय को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रस्ताव को 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने स्वीकृति दी थी।
- राज्य सरकार द्वारा किन्नरों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के परिपालन में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर इन्हें पिछड़ा माना जाता है।
- सामाजिक न्याय विभाग के अनुसार प्रदेश में किन्नरों की प्रमाणित संख्या नहीं है। जबकि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने करीब 6 हजार किन्नरों की संख्या दर्ज की है, जिसमें कुछ जिलों में सुधार भी किया गया है।
- प्रदेश में चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में 1432 किन्नर दर्ज हैं। इसमें सबसे ज्यादा 176 किन्नर भोपाल में हैं, जबकि उज्जैन में 75, इंदौर में 102 दर्ज हैं।
- उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी, 2023 को राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2021 (Transgender Protection of Rights Rules-2021) के तहत आदेश जारी कर नौकरियों में सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये अलग श्रेणी बनाई है। इसके साथ ही अब सरकारी नौकरियों के लिये आवेदन पत्र में पुरुष और महिला के साथ ट्रांसजेंडर का विकल्प भी उपलब्ध हो गया है।

मध्य प्रदेश पुलिस के दो प्रशिक्षण संस्थानों को मिलेगी यूनिन होम मिनिस्टर ट्रॉफी

चर्चा में क्यों ?

19 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस के दो प्रशिक्षण संस्थानों- पुलिस अकादमी भौरी और पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी को पुलिस के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली यूनिन होम मिनिस्टर ट्रॉफी के वर्ष 2021-22 के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में अलंकरण समारोह यूनिन होम मिनिस्टर ट्रॉफी से सम्मानित किये जाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों को ट्रॉफी एवं प्रमाण-पत्र के साथ 2 लाख रुपए की नगद राशि भी प्रदान की जाएगी।
- पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी की ओर से श्रीमती निमिषा पांडेय एवं मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी भोपाल की ओर से मलय जैन यह सम्मान प्राप्त करेंगे।
- पश्चिम जोन के लिये आरक्षकों का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी एवं उप पुलिस अधीक्षकों की सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण अकादमी, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी को चुना गया है।
- प्रशिक्षण में नव प्रयोग तथा आधुनिक तकनीक का समावेश कर देश के पुलिस प्रतिभागियों को प्रशिक्षण का लाभ देने में मध्य पुलिस पुलिस अग्रणी रही है। प्रशिक्षण विशेषज्ञों को जोड़ने के लिये देश-विदेश के विश्वविद्यालयों एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एम.ओ.यू. एवं विशेषज्ञता के आदान-प्रदान से उत्तम कोटि के परिणाम सामने आए।
- उल्लेखनीय है कि देश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण का आकलन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एवं डेवलपमेंट द्वारा निर्धारित मानकों पर किया जाता है।
- इसमें आरक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान एक कैटेगरी में तथा उप निरीक्षक एवं पुलिस उप-अधीक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान अलग-अलग कैटेगरी में रखकर निर्धारित मापदंड पर बेहतर प्रशिक्षण पद्धति, संसाधनों का समुचित रख-रखाव एवं वर्ष भर में उत्कृष्ट प्रशिक्षण क्षमता प्रदर्शित करने वाले प्रशिक्षण संस्थान का चयन राष्ट्रीय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जाता है।

जल जीवन मिशन में ज़िला बुरहानपुर 'प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार' से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

21 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस पर गरिमापूर्ण समारोह में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में देश में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले बुरहानपुर जिले को 'प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार' से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- बुरहानपुर जिले की कलेक्टर सुश्री भाव्या मित्तल ने प्रधानमंत्री के हाथों से यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- बुरहानपुर जिले ने जल जीवन मिशन से हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुँचाने की अभूतपूर्व और गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। बुरहानपुर को देश में पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है।
- हर गाँव में पानी पहुँचाकर बुरहानपुर ने देश को एक नई दिशा दिखाई है। जल जीवन मिशन में अब तक प्रदेश के 51 लाख 15 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। सभी 254 गाँव में 'हर घर जल' योजना से पानी पहुँचाया जा रहा है।
- बुरहानपुर जिले में जल जीवन मिशन 'हर घर जल' योजना पंचायतों द्वारा संधारित और संचालित की जा रही है। प्रत्येक गाँव में जल स्वच्छता तदर्थ समिति गठित की गई है, जो योजना का संधारण और क्रियान्वयन करती है। सभी गाँव के वॉटरमेन और प्लंबर को विधिवत प्रशिक्षण दिया गया है।
- प्रशासन द्वारा पंचायतों में कौशल विकास के लिये 'नल जल प्रबंधन' पुस्तिका तैयार की गई है, जिसमें योजना के संचालन की विस्तृत जानकारी है।

- योजना में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जल कर वसूली का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य से महिलाओं को रोजगार मिला है, वहीं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है।
- पंचायतों, ग्रामीणों को भूमिगत जल-संरक्षण के लाभों के प्रति जागरूक करते हुए इसे सहेजने के तरीके बता रही हैं। शासन-प्रशासन के साथ आम लोगों की उत्साहपूर्वक भागीदारी से बुरहानपुर जिले ने देश में अपना परचम लहराया है।

निर्वाचन की राज्य स्तरीय आईकॉन नियुक्त हुई समाज सेविका थर्ड जेंडर संजना सिंह

चर्चा में क्यों ?

21 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने समाजसेविका थर्ड जेंडर संजना सिंह को मध्य प्रदेश निर्वाचन का राज्य स्तरीय आईकॉन नियुक्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- समाजसेविका थर्ड जेंडर संजना सिंह पुष्पा नगर बावड़ी चांदबड़ की रहने वाली हैं।
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में निवासरत थर्ड जेंडर मतदाता, मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक सहभागिता निभाएँ, इसके लिये थर्ड जेंडर संजना सिंह को राज्यस्तरीय आईकॉन बनाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि संजना सिंह इससे पहले मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा पहली ट्रांसमेंटोर चुनी गई थीं। वे स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता अभियान मध्य प्रदेश की पहली थर्ड जेंडर थीं, जो ब्रांड एंबेसडर बनीं।
- इसके अलावा संजना सिंह को साल 2017 में डेटॉल स्वच्छ भारत बनेगा भारत लाइव-शो में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ह्वाट्सएप से बिल जमा करने वाली देश की पहली कंपनी

चर्चा में क्यों ?

21 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली सरकारी बिजली वितरण कंपनी है, जो ह्वाट्सएप-पे के माध्यम से ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान का अभिनव प्रयास शुरू कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि बिजली बिलों के भुगतान के डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाते हुए सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान की दिशा में कंपनी ने उपभोक्ताओं को एक दर्जन से अधिक बिल भुगतान के विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इसी कड़ी में ह्वाट्सएप-पे के माध्यम से एक नया विकल्प उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध हो जाएगा। इस नये तरीके से उपभोक्ता अपने स्मार्ट फोन का उपयोग कर अपने घर से ही बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे।
- 'ह्वाट्सएप-पे' एक डिजिटल पेमेंट फीचर है, जो यूजर्स को मैसेजिंग एप के जरिये पैसे भेजने की सुविधा देता है। यह सुरक्षित और उपयोग में आसान है, लेन-देन को पूरा करने के लिये बस कुछ सरल चरणों की आवश्यकता होती है।
- उपभोक्ता बिना किसी परेशानी के भुगतान करने के लिये अपने मौजूदा ह्वाट्सएप खाते का उपयोग कर सकते हैं और इसे अपने बैंक खाते से जोड़ सकते हैं।
- जिस उपभोक्ता के पास 'ह्वाट्सएप-पे' सुविधा नहीं है, वे ह्वाट्सएप से गूगल-पे, फोन-पे या पेटीएम जैसे अन्य यूपीआई मोड के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। इस अभिनव भुगतान पद्धति के लिये किसी अतिरिक्त डाउनलोड या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- गौरतलब है कि भुगतान के इस नए तरीके से न केवल उपभोक्ताओं को अपने बिलों का भुगतान करना आसान होगा, बल्कि इससे समय और मेहनत की भी बचत होगी।

- ह्वाट्सएप-पे और अन्य ऑनलाइन भुगतान विकल्पों के साथ उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिये कैश कलेक्शन सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह एक तेज और कुशल समाधान है, जो भुगतान प्रक्रिया को सरल करेगा और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार आएगा।
- उल्लेखनीय है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने उपभोक्ताओं के लिये ह्वाट्सएप चैटबॉट को लागू करने वाली पहली बिजली वितरण कंपनी है, जिसके माध्यम से कोई भी बिजली बिल देख सकता है, भुगतान, रसीद एवं शिकायत कर सकता है, स्थिति को पता कर सकता है।

सरोगेसी अधिनियम के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल

चर्चा में क्यों ?

24 अप्रैल, 2023 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई राज्य सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड की बैठक में यह जानकारी दी गई कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम-2021 के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में बताया गया कि अधिनियम में राज्य बोर्ड, जिला समुचित प्राधिकारी और जिला अपीलीय अधिकारी को अधिसूचित करने संबंधी कार्य करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।
- प्रदेश में अधिनियम के अधीन 74 संस्थाओं का पंजीयन किया गया है। इन संस्थाओं में एआरटी बैंक, एआरटी लेवल-1 क्लीनिक, एआरटी लेवल-2 क्लीनिक और सरोगेसी क्लीनिक शामिल हैं।
- अधिनियम में सरोगेसी प्रक्रिया के लिये प्रोसेस फ्लो और विभिन्न प्रारूपों के निर्धारण में भी मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।

मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभयारण्य होगा चीतों का नया घर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार अफ्रीकी देश नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के श्योपुर कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य (केएनपी) में रखे गए चीतों के लिये अब गांधी सागर अभयारण्य को विकसित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गांधी सागर अभयारण्य को चीतों के लिये विकसित किया जा रहा है और अगले छह महीने में यह बनकर तैयार हो जाएगा।
- वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वन्यजीव सलाहकार बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन अधिकारियों को अगले छह महीनों में गांधी सागर अभयारण्य को चीतों के नए घर के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है।
- मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि गांधी सागर में नामीबिया से लाए गए चीतों के लिये नया निवास स्थान बनाने हेतु शिवराज सिंह चौहान सरकार की ओर से यह कदम विशेषज्ञों के सुझाव के बाद उठाया गया है। विशेषज्ञों ने सरकार को सुझाव दिया है कि कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य नामीबिया से लाए गए सभी चीतों के लिये पर्याप्त नहीं है।
- चीतों के नया घर बनाने के लिये गांधी सागर अभयारण्य को विकसित करने में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। वन विभाग ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) से इस संबंध में निर्णय लेने को कहा था।

मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 स्थगित

चर्चा में क्यों ?

- 25 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 21 अप्रैल, 2023 को प्रदेश के नगरों की सीमाओं के भीतर व्यापार करने के विनियमन के लिये मध्य प्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 अधिसूचित किया गया था।
- इन नियमों के लागू होने के पहले जिन नगरीय निकायों द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 अथवा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निकाय स्तर पर व्यापार विनियमन के लिये व्यापार अनुज्ञापित (ट्रेड लायसेंस) जारी करने के लिये शुल्क निर्धारित करके नियम लागू किये गए हैं, वह पूर्वानुसार लागू रहेंगे।
- उल्लेखनीय है कि नवीन नियमों के प्रकाशित होने के बाद विभिन्न नगरों के संबद्ध व्यवसायियों, व्यापार समूहों एवं निकायों के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा नियमों में विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था।

केबिनेट में पन्ना की दो सिंचाई परियोजना को मिली पुनर्ीक्षित स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

- 25 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पन्ना जिले की दो सिंचाई परियोजना- रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना और मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना को पुनर्ीक्षित स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु

- रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना में सिंचाई का क्षेत्र 14 हजार 450 हेक्टेयर है। परियोजना के लिये 513 करोड़ 72 लाख रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना से अजयगढ़ तहसील के 47 गाँवों को 14 हजार 450 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।
- इसी प्रकार मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना में सिंचाई का क्षेत्र 1360 हेक्टेयर है। परियोजना के लिये 693 करोड़ 64 लाख रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना से पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के 38 गाँवों को 1360 हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ मिलेगा।

राज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी उद्घाटित

चर्चा में क्यों ?

26 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कनवेंशन सेंटर में दो दिवसीय आईसेक्ट राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। संगोष्ठी का आयोजन आत्मनिर्भर भारत के लिये सामाजिक उद्यमिता और कौशल विकास विषय पर चर्चा के लिये किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर आईसेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट के मध्य सामाजिक उद्यमिता पर पारस्परिक समझौता किया गया। साथ ही युवा उद्यमियों का सम्मान भी किया गया।
- रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे ने बताया कि मध्य भारत का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय आईसेक्ट द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यह संस्थान का छठा विश्वविद्यालय होगा।

- उन्होंने बताया कि आईसेक्ट सामाजिक उद्यमिता पर आधारित 37 हजार केंद्रों का 27 राज्यों में संचालन कर रहा है। केंद्र का मॉडल भारतीय भाषाओं और सोशल कनेक्ट पर आधारित है। तकनीक के साथ कृषि के क्षेत्र में भी संस्थान द्वारा पहल की गई है।
- आईसेक्ट के सचिव डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने संगोष्ठी की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संगोष्ठी का आयोजन शृंखला में किया जा रहा है। इसी तरह की 15 कॉन्फ्रेंस का आईसेक्ट द्वारा आयोजन किया जाना है।
- संगोष्ठी में बताया गया कि देश में ज्ञान आधारित डिजिटल अर्थ-व्यवस्था भविष्य की प्रौद्योगिकी में नवाचार लॉजिस्टिक्स रक्षा अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप के लिये नये अवसर निर्मित हुए हैं।
- हरित हाइड्रोजन मिशन को 20 हजार करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले वर्षों में रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा है। कृषि बजट भी 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। औषधियों के क्षेत्र में अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिये उत्कृष्टता केंद्रों के जरिये नया कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- सरकार, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कौशल प्रशिक्षण के लिये देश में 30 स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, तीन कृत्रिम मेधा उत्कृष्टता केंद्र और फाइव जी एप्लीकेशन विकास के लिये 100 प्रयोगशालाएँ खोल रही हैं।



कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में तीन दिवसीय इंटरनेशनल वाईल्ड लाईफ कॉन्फ्रेंस

चर्चा में क्यों ?

26 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश जन संपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 27 से 29 अप्रैल तक 'इंटरनेशनल वाईल्ड लाईफ कॉन्फ्रेंस' का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रदेश में वानिकी अनुसंधान का एक शतक पूरे होने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नर्मदापुरम में 27 मार्च, 2022 को की गई घोषणा के अनुरूप किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में वन्य-जीव विशेषज्ञ-पैशुषण डॉ. एच.एस. पवार सहित दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के ख्यातिलब्ध वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं।

- आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री के उद्देश्यों के अनुरूप इकोनॉमी और इकोलॉजी की नीति को अपनाते हुए देश के सर्वांगीण विकास के लिये निष्कर्ष निकालना कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है।
- वन विभाग और राज्य वन अनुसंधान 'वन्य-जीव संरक्षण उभरता परिदृश्य एवं इस भावी रणनीति' विषय पर वन्य-प्राणी प्रबंधन-संरक्षण, पुनर्वास और मध्य प्रदेश सहित भारत में एक आदर्श पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिये इस क्षेत्र के विशेषज्ञ, शोधकर्ता और पेशेवर 4 तकनीकी विषय पर शोध पत्र एवं वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे।
- इसके साथ ही वन्य-प्राणी प्रबंधन, संरक्षण और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वर्तमान परिदृश्यों पर गहन मंथन कर भविष्य की रणनीति और नीतियाँ तय की जाएंगी।
- कॉन्फ्रेंस, वन्य-जीव जनसंख्या प्रबंधन, वन्य-जीव आवास पारिस्थितिकी, वन्य-जीव नीति के मुद्दे चुनौतियाँ और मानव वन्य-जीव संघर्ष और शमन उपाय जैसे तकनीकी विषयों पर होगी।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले सात नए जज, अब संख्या बढ़कर हुई 37

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सात नए जजों की नियुक्ति को लेकर भारत सरकार के विधि एवं न्यायिक विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं। इससे प्रदेश के हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है, लेकिन अब भी स्वीकृत में से 16 पद रिक्त हैं।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सात नए जजों की पदस्थापना की गई है। इसमें रूपेश चंद्र वशने, अनुराधा शुक्ला, संजीव सुधाकर कलगावकर, प्रेम नारायण सिंह, अचल कुमार पालीवाल, हृदेश व अरविंद कुमार सिंह के नाम शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है, जिसमें से वर्तमान में चीफ जस्टिस को मिलाकर 30 जज कार्यरत हैं।
- लंबे समय से हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की मांग की जा रही थी। इसके बाद उक्त नामों की सिफारिश की गई और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधि एवं न्यायिक विभाग ने उक्त नामों को हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त किये जाने के आदेश जारी किये हैं।



मध्य प्रदेश हाईकोर्ट